आकाशवाणी शिमला
17.07.2025 / प्रादेशिक समाचार / 09:20बजे

राष्ट्रपति–स्वच्छ सर्वेक्षण

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में प्रतिष्ठित स्वच्छ सर्वेक्षण 2024–25 पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस कार्यक्रम में शहरी भारत के सबसे स्वच्छ शहरों को सम्मानित किया जायेगा और स्वच्छ भारत मिशन–शहरी को आगे बढ़ाने के प्रयासों को मान्यता दी जायेगी। इस वर्ष ये पुरस्कार चार श्रेणियों में प्रदान किए जाएंगे, जिनमें सुपर स्वच्छ लीग शहर और अधिक जनसंख्या वाले पांच शहरों में से शीर्ष तीन स्वच्छ शहर शामिल हैं। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने कहा है कि इस वर्ष कुल 78 पुरस्कार प्रदान किए जाएँगे। मंत्रालय ने कहा है कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2024–25 में शहरी स्वच्छता और सेवा वितरण का आकलन करने के लिए एक स्मार्ट और सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाया गया है, जो शहरों में स्वच्छता और अपशिष्ट प्रबंधन का संपूर्ण दृश्य प्रस्तुत करता है।

अश्विनी– सीएससी दिवस

इलेक्ट्रॉनिक्स व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि देश के दस लाख नागरिकों को निःशुल्क आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रशिक्षण दिया जाएगा और इसमें ग्राम स्तर के उद्यमियों को प्राथमिकता दी जाएगी। उन्होंने डिजिटल इंडिया के 10 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में नई दिल्ली में आयोजित जन सेवा केन्द्र दिवस कार्यक्रम में यह घोषणा की। उन्होंने कहा कि सी एस सी देश के लगभग 90 प्रतिशत गाँवों तक पहुँच चुका है। वैष्णव ने सभी ग्रामीण उद्यमियों से नागरिकों को आई आर सी टी सी सेवाएँ प्रदान करने का आग्रह किया।

जगत सिंह नेगी

राजस्व व बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा है कि प्रदेश में प्राकृतिक आपदा से भूमिहीन हुए लोगों को रहने व खेती के लिए जमीन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने केंद्र से एफसीए एक्ट 1980 में संशोधन की मांग की है। शिमला में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि इस मामले को लेकर राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका भी दायर करेगी।

विरोध प्रदर्शन

सीटू और किसान सभा के बैनर तले शिमला फोरलेन के प्रभावितों ने चक्कर स्थित एन.एच.ए.आई. के दफ्तर के सामने विरोध प्रदर्शन किया। सीटू के प्रदेश अध्यक्ष विजेन्द्र मेहरा ने कहा कि फोरलेन निर्माण कर रही कम्पनियों द्वारा अवैज्ञानिक तरीके से सड़क निर्माण का कार्य किया जा रहा है जिससे कैथलीघाट से ढली तक 9 पंचायतों के लोग प्रभावित हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि अवैज्ञानिक कटिंग और अवैध डम्पिंग से लोगों के घर, खेत, रास्ते और पेयजल स्रोत प्रभावित हुए हैं।

सुर्खियां समाचार पत्रों से

अमर उजाला की सुर्खी है **कड़छम–वांगतू से हिमाचल को मिलेगी 18 प्रतिशत रॉयल्टी, 2 सौ 50 करोड़ होगी आय।**

रेरा का कार्यालय शिफ्ट करने पर रोक शीर्षक से दैनिक जागरण लिखता है **हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान दिए आदेश।**

पंजाब केसरी की एक खबर है **मंत्रिमंडल बैठक में आपदा प्रभावितों के लिए तैयार होगा पैकेज का खाका।**